भारत के गरीबों को कम मुद्रास्फीति जोखिम का सामना करना पड़ता है: यूएन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

- हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की 'एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज' शीर्षक से किए गए एक अध्ययन के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। फलतः कई विकसित और अमीर देश में निम्न आय वर्ग एवं गरीब वर्ग के लोग और गरीब हो गए।

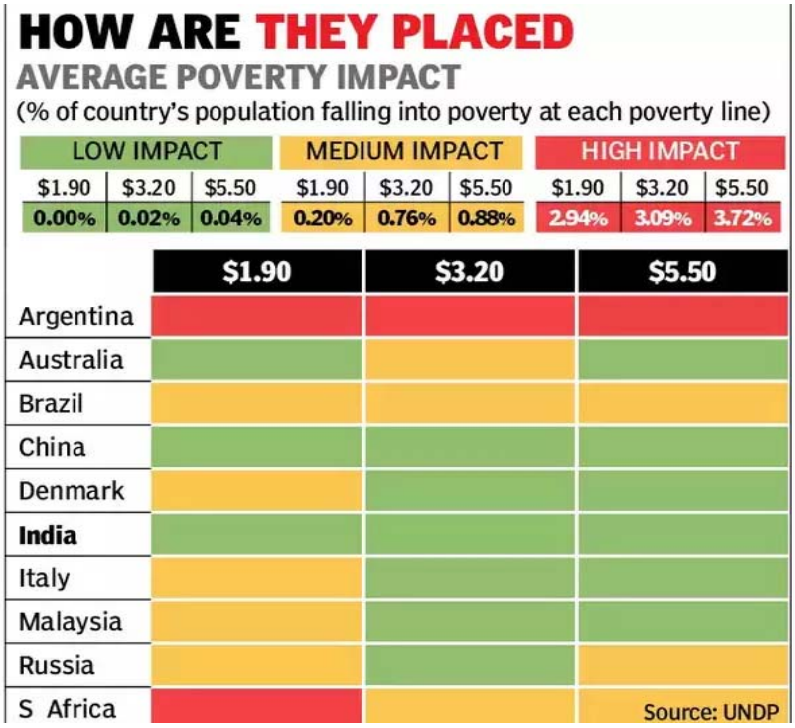

रिपोर्ट के मुख्य अंश

विश्व संदर्भ में निष्कर्ष

- **बढ़ती गरीबी पर अनुमान**

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने इस नई रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि वैश्विक खाद्य व ऊर्जा क़ीमतों में आए तेज़ उछाल के कारण मार्च 2022 के बाद के तीन महीनों में विकासशील देशों में सात करोड़ 10 लाख से अधिक लोग निर्धनता के गर्त में समा गए हैं।
- यूएन एजेंसी के अनुसार, यूक्रेन में युद्ध के कारण इसका प्रभाव निर्धनता दर पर हुआ है।
- कोविड-19 महामारी का प्रभाव गरीबी पर भी पड़ा है।
- कैस्पियन बेसिन, बाल्कन और उप-सहारा अफ्रीका के साथ गरीबी के अधिकतम प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- अध्ययन में एक प्रभावी उपकरण के रूप में लक्षित और समयबद्ध नकद हस्तांतरण का समर्थन किया गया है।

- पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए जोखिम कारक
  - इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आकलन के अनुसार, पाकिस्तान और श्रीलंका उन देशों में शामिल हैं, जो उच्च गरीबी प्रभावों का सामना कर रहे हैं।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों में औसतन लगभग 3% आबादी गरीबी में गिर सकती है।

मूल्यांकन

- यूएनडीपी ने महंगाई और खाद्य संकट से प्रभावित तीन प्रकार के निम्न आय वर्गों से जुड़े लोगों का मूल्यांकन किया।
- इनमें रोजाना 152 रुपये, 264 रुपये व 440 रुपये खर्च करने वाले लोगों को शामिल किया गया था।
- रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग देशों में अलग-अलग आय वर्ग के लोग बढ़ती महंगाई और खाद्य वस्तुओं के संकट से प्रभावित हुए।

भारत के संदर्भ में अवलोकन

- भारत में प्रतिदिन 1.9 डॉलर कमाने वालों के गरीबी में गिरने की संभावना शून्य होगी।

- यदि गरीबी रेखा क्रमशः $3.30 या $5.50 प्रति दिन मान ली जाए तो यह प्रभाव मात्र 0.02% और 0.04% होगा।
- भारत में समग्र प्रभाव नगण्य है।
- विदित है कि वर्ष 2020 के अप्रैल महीने से सरकार लगातार 80 करोड़ लोगों को पांच किलोग्राम मुफ्त राशन दे रही है और यह कार्यक्रम इस साल सितंबर तक जारी रहेगा।
- कोरोना काल में जन-धन खाता रखने वाली 20 करोड़ महिलाओं को 1500-1500 रुपये उनके खाते में सरकार की तरफ से हस्तांतरित किए गए।
- अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक, सरकार ने पीएमजीकेएवाई के लिए 1,003 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है, जिससे ढाई साल के लिए 80 करोड़ का लाभ हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

- अंतर्राष्ट्रीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी के रूप में यूएनडीपी 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करती है।
- यूएनडीपी 1949 में बनाए गए तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तारित कार्यक्रम और 1958 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय पर आधारित है।
- यह विभिन्न देशों को नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में सहायता करता हैं।
- यह तीन फोकस क्षेत्रों पर केंद्रित है
    - सतत विकास
    - लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण
    - जलवायु और आपदा लचीलापन।
- लक्ष्य और दूरदर्शिता
    - यूएनडीपी का जनादेश गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन, कानून का शासन और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है।
    - यह सकारात्मक परिवर्तन का पक्षधर है और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को साझा करता है।

स्रोत: द हिन्दू

भारत का राष्ट्रीय प्रतीक

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**प्रथम प्रश्न पत्र :** भारतीय संस्कृति- प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू।

संदर्भ

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

सेंट्रल विस्टा परियोजना

- पुराने भवन की स्थिरता की चिंताओं के दृष्टिगत वर्ष 2010 में मौजूदा भवन को बदलने के लिए नए संसद भवन के प्रस्ताव के लिए एक समिति की स्थापना तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की थी।
- भारत सरकार ने 2019 में एक नए संसद भवन के निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के लिए नया कार्यालय और संसद भवन की संकल्पना के साथ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू हुई।

- नए भवन के लिए भू-निर्माण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी।

सेंट्रल विस्टा परियोजना की विशेषताएँ

- सेंट्रल विस्टा के वास्तुकार प्रभारी बिमल पटेल हैं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कारिडोर के काम को भी पूरा किया है।
- संसद का नया परिसर त्रिकोणीय आकार का होने के साथ ही मौजूदा भवन से काफी बड़ा है।
- इस भव्य इमारत का 150 से अधिक वर्षों का जीवन होगा। साथ ही, इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है।
- पूरे भवन में भारत के विभिन्न हिस्सों से वास्तुशिल्प शैलियों को शामिल किया गया है।
- ध्यातव्य है कि सांसदों की बढ़ती संख्या और भविष्य के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए नए परिसर में लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी।

राष्ट्रीय प्रतीक

- वाराणसी में सारनाथ के पुरातात्विक खंडहर परिसर में बौद्ध कालीन यह स्तंभ परिसर में ही पहले मौजूद था। बाद में पत्थरों से निर्मित सिंह शीर्ष यानी खंबों से ऊपर के हिस्से को सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में सामने स्थापित कर दिया गया।
- सारनाथ में मौजूद इस अशोक की लाट को आजाद भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर शामिल किया गया। जबकि आज भी इसका मूल प्रारूप सारनाथ के खंडहर परिसर में खंबों के रूप में संरक्षित है, तो दूसरी ओर संग्रहालय में इसके शीर्ष को संरक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतीक की विशेषताएं

- धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक धर्मसंघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह मीरजापुर में चुनार के लाल बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे पत्थर का बना हुआ है। जमीन में गड़े आधार को छोड़कर इसका आकार गोलाकार है। सिंह शीर्ष के ठीक कंठ के नीचे उलटा कमल है।

- गोलाकार कंठ चक्र से चार भागों में हाथी, घोड़ा, सांड़ और ऊपर सिंह की गर्जना करते सजीव आकृतियां हैं।
- ऊपर शीर्ष में चार सिंह मूर्तियां हैं, जो पीछे से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
- इन चारों के बीच में एक छोटा दंड 32 तीलियों का है, जो धर्मचक्र को धारण करने का प्रतीक है।
- स्तंभ का पूरा निचला भाग अपने मूल स्थान पर कांच में सुरक्षित रखा गया है, जबकि शेष सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है।

स्रोत: द हिन्दू

सेना के लिए एआई-आधारित मंदारिन अनुवाद उपकरण

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा

संदर्भ

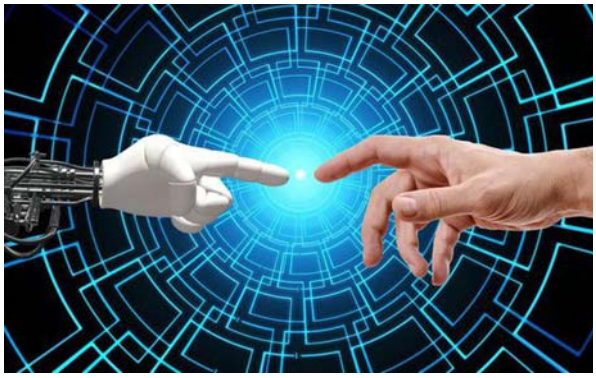

- पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से जारी विवाद के दृष्टिगत सेना ने करीब 3,400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट सतर्कता बढ़ाने की समग्र नीति के अंतर्गत अपने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के प्रयास तेज कर दिए है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- सेना की उत्तरी, पूर्वी और मध्य कमान के भाषा स्कूलों में मंदारिन भाषा संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

- भारतीय सेना मंदारिन भाषा से विभिन्न लेखों या साहित्य के अनुवाद के लिए कृत्रिम मेधा आधारित समाधानों का भी उपयोग कर रही है।
- सेना ने प्रादेशिक सेना में मंदारिन-प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक अनुमोदन हाल में प्राप्त किए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डिवाइस

- यह एक भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित 600 ग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डिवाइस की मदद से संभव होगा
- वर्तमान में सेना के साथ उन्नत परीक्षणों के तहत, यह 'एआई इन डिफेंस' संगोष्ठी में अनावरण किए गए 75 एआई-सक्षम उत्पादों और अनुप्रयोगों में से एक था।
- "यह एक ऑफ़लाइन हैंडहेल्ड भाषा अनुवाद प्रणाली है, जो एआई पर आधारित है।
- यह 5-10 फीट की सीमा के साथ द्विदिश है और मंदारिन को अंग्रेजी में परिवर्तित करता है।
- पहला प्रदर्शन 2017 में किया गया था और तब से लेकर अब तक इसके कई ट्रायल हो चुके हैं।

आवश्यकता

- प्रतिष्ठान के भीतर मंदारिन में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, ताकि कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कमांडर आवश्यकता पड़ने पर चीनी सैन्य कर्मियों से संवाद कर सकें।
- कोर कमांडर स्तर की वार्ता, फ्लैग मीटिंग, संयुक्त अभ्यासों और सीमा कार्मिक बैठकों (बीपीएम) जैसे विभिन्न स्तर के संवाद के दौरान चीनी पीएलए की गतिविधियों के बारे में उनकी बात को बेहतर तरीके से समझने और विचारों का बेहतर तरीके से आदान-प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में मंदारिन विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

किए जा रहे प्रयास

- पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद एलएसी पर समग्र निगरानी बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों ने पिछले दो वर्षों में कई कदम उठाए हैं।

- मंदारिन भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए हाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजी) और शिव नाडर विश्वविद्यालय (एसएनयू) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रतिष्ठान के भीतर किए जा रहे प्रयासों के तहत पचमढ़ी स्थित सैन्य प्रशिक्षण स्कूल और विदेशी भाषा स्कूल, दिल्ली में रिक्तियों को बढ़ाना शामिल है।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भाषाविदों की दक्षता के स्तर का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित सैनिकों की दिल्ली में 'लंगमा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज' जैसे नागरिक संस्थानों के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाती है।

स्रोत: द हिन्दू